



- आधार और चुनाव संबंधी डेटाबेस के बीच प्रस्तावित लैकिंग ECI और [भारतीय वशिष्ट पहचान प्राधिकरण \(UIDAI\)](#) को डेटा उपलब्ध कराएगा।
- इससे नागरिकों की नजिता का हनन हो सकता है।

■ **सरकार का रुख:**

- **सर्वेच्छक लैकिंग:** आधार और चुनाव डेटाबेस के बीच प्रस्तावित लैकिंग सर्वेच्छक है।
- **मताधिकार से वंचित होने का कोई जोखिम नहीं:** मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिये कयि कसिी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं कयिा जाएगा और कसिी वयक्तद्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचति करने में असमर्थता की स्थतिमें मतदाता सूची से कोई भी प्रवषिटि नहीं हटाई जाएगी।

## आगे की राह

- **व्यापक कानून की आवश्यकता:** एक तुरुटि मुक्त मतदाता सूची स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव के लयि अनविर्य है। यद्यपि सरकार को चाहयि कि वह इसके लयि व्यापक वधियक प्रस्तुत करे ताकि संसद में इस मुद्दे पर उचति चर्चा हो सके।
- **अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता:** वधियक में दो डेटाबेस के बीच डेटा साझाकरण की सीमा, ऐसे तरीके जनिके माध्यम से सहमति प्राप्त की जाएगी और कया डेटाबेस को जोड़ने के लयि सहमति रद्द की जा सकती है, जैसी बातों को नरिदषिट कयिा जाना चाहयि।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/election-laws-amendment-bill-2021>

